ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 76-77

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16 YEAR- June. -2020

भारत में ग्रामीण गरीबी एवं रोजगार के बदलते स्वरूप

रूपाली नाग

शेध अध्येता – समाजशास्त्र विभाग, नागरिक पी0जी0 कालेज, जंघई – जौनपुर (उ0प्र0), भारत

Received- 29.02.2020, Revised- 05.03.2020, Accepted - 11.03.2020 E-mail: rupalinag1282@gmail.com

सारांश : अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में तेजी से गरीबी कम करने वाले दस राष्ट्रों में भारत देश का नाम भी जुड़ गया है। उस रिपोर्ट में यह भी लिया गया है कि हमारा देश भारत 2030 तक लगभग 25 मिलियन परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में सफल रहेगा । यह सब इस समय की मोदी सरकार की वजह से भी हो पा रहा है, क्योंकि पहले भी तमाम सरकार बनी, उन्होंने तमाम विकास सम्बन्धी योजनायें चलाई, लेकिन मोदी सरकार ने योजनाएं तो चलाई ही साथ ही उन योजनाओं पर अधिक से अधिक कार्य किया। जिससे आम ग्रामीण जनता उनका लाभ उठा सके। क्योंकि भारत देश में कुल जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, जिसमें अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धनता का एक कारण है कि आम जनता तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाना।

कुंजीभूत शब्द– योजनाएं, जनसंख्या, निर्धनता, ग्रामीण क्षेत्रों, गरीबी, संसाधनों, मिड डे मिल, सामाजिक, निर्धन।

हमारे देश में ऐसे राज्य है जैसे– उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, झारखण्ड आदि जहां एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग है, जिन्हें एक वक्त का भोजन ही बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। लेकिन पिछले कुछ समय से गरीबी दूर करने के लिए हमारी मोदी सरकार ने ऐसी योजनायें चलाई है, जिससे ग्रामीण जनता को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी मेल्टी डायमेंशनल पावटी इंडेक्स–2018 के मुताबिक 2005–06 से लेकर 2015–16 के बीच भारत में 28 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ गए है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आज के आधुनिक तकनीकी के द्वारा रोजगार के साधन उपलब्ध तरह–तरह के नये संसाधनों को मार्केट में उपलब्ध कराना।

दूसरी तरफ हाल ही में ब्रुकिंग्स के यूचर डेवलपमेंट ब्लॉग में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, हर मिनट में 44 भारतीय अत्यन्त गरीबी की श्रेणी से बाहर निकलते जा रहे है। यह आंकड़ाँ दुनिया में गरीबी घटने की सबसे तेज रतार को इंगित करती है। इसका प्रमुख कारण है कि बाते पांच सालों में मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना जैसे–जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना आदि।

ये सभी योजनायें ग्रामीण गरीबी को कम करने में बहुत ही कारगर साबित हुई है। एक तरफ यह भी देखा गया कि ग्रामीण गरीबी में काफी कमी आयी है, लेकिन फिर भी शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग निर्धन है। यद्यपि निश्चित ही गरीबों की स्थिति में बदलाव के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का असर भी हो रहा है। विश्व सामाजिक सुरक्षा के तहत रोजगार प्रदान करने में विश्व बैंक ने मनरेगा को पहले स्थान पर माना है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे भारत के सबसे अधिक पंद्रह करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है।

इसी तरह मिड डे मिल येाजना को भी सबसे बड़ा विद्यालयी कार्यक्रम कहते हुए इसकी सराहना की गई है।

इससे 10.5 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे है। लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है, वास्तविकता यह भी है कि मिड–डे–मिल योजना और मनरेगा भ्रश्टाचार का भी आज शिकार हो रही है।

देश में स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। वही करीब सत्ताईस करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे है। भारत में सबसे अधिक निर्धन लोग बिहार, झारखण्ड, ओड़िसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि में रहते है। लिहाजा इन राज्यों के लिए कुछ विशेष योजनायें बननी चाहिए। जिससे इन गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को कुछ फायदा हो।

वैसे पिछले कुछ समय में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विकास, आजीविका में विविधता लाने, गरीबी कम करने और इसके माध्यम से गरीब परिवारों में खुशहाली बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के वित्तीय संसाधनों के आवंटन में काफी बढ़ोत्तरी की गई है। वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रकोप सबसे अधिक होता है।

इसी बात को ध्यान में रखने के लिए प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है, जो इस वर्श में काफी हद तक फलीभूत होगी। ग्रामीण विकास होने से शहरों की ओ पलायन कम होगा और रोजगार की संभावनाओं का सृजन होगा। एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाएं भी गरीबी

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16 YEAR- June. -2020

उन्मूलन की दिषा में रामबाण का काम करेगी।

गरीबी उन्मूलन को लेकर चल रही यह योजनाएं–

- अन्नपूर्णा योजना।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना।
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना।
- ग्रामीण श्रम रोजगार गारंटी योजना।
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना।
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था लाभ योजना।
- बंधुआ मुक्ति मोर्चा।
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
- ग्रामीण आवास योजना।

बैंकों द्वारा सरकारी नीतियों के आधार पर गरीबी उन्मूलन का कार्य किया जा रहा है। बैंकों द्वारा बी0पी0एल0 कटेगरी को सस्ता कर्ज मुहैया कराया जा रहा है। वही फसल बीमा योजना का लाभ भी किसानों को दिया जा रहा है। रूडसेट संस्थान गरीबी उन्मूलन की दिशा में लगातार प्रयासरत है। वर्ष 2018 इस मामले में काफी खास होने जा रहा है। इस संस्थान द्वारा निःषुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें आटो मोबाइल, रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशन फोटो एड वीडियों–इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई, ब्यूटीपार्लर व डीटीपी सहित अन्य ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां से अब तक प्रशिक्षण लेने वाले सभी स्वावलंबी है। इस तरह से आज भारत देश रोजगार का स्वरूप बदल रहा है। लोग काफी कम समय में मेहनत करके ही पर्याप्त धन कमा रहे है और इस प्रकार से गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राय – सुधीर कुमार;ग्रामीण समाजिक संरचना और पीर्रवतन, नीलकमल प्रकाशन, गोरखपुर 2006।
2. मालविया – एच0डी0; भारत में पंचायती राज, 1 956, नई दिल्ली।
3. श्रीवास्तव, डॉ0 राजीव कुमार; वैश्वीकरण एवं भारत, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी।

*****